देशबन्धु
अवकाश अंक

रविवार, 4 जून 2017 | रायपुर | बिलासपुर | भोपाल | जबलपुर | सतना | दिल्ली | सागर

बौने कद के ऊंचे लोग 3
मेरी कालजयी रचना 2
नूतन को याद करता सिनेमा 4

शिक्षक की अनुपस्थिति को एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाना सरकारी स्कूली शिक्षातंत्र को और बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देख सकते हैं कि शिक्षकों की अनुपस्थिति को रोकने के लिए सरकार की ओर से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया। बायोमेट्रिक प्रणाली में शिक्षक को अपने प्रमाण देने होते हैं कि वह स्कूल में मौजूद है या नहीं। जहां शिक्षक मोबाइल के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली की यह व्यवस्था शिक्षकों पर शक करने से ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार शिक्षकों पर मुहर लगा दी जाती है कि सभी शिक्षक बेईमान हैं। जबकि अध्ययन बताता है कि केवल 2.5 फीसदी शिक्षक ही बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं। बाकी के शिक्षक तंत्रगत कार्य से कर्तव्य पर रहते हुए स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं।

सरकारी स्कूल के शिक्षकों की अनुपस्थिति पर एक अध्ययन

निशाने पर सरकारी स्कूली शिक्षातंत्र

■ कालू राम शर्मा

सरकारी स्कूल तंत्र, शिक्षक, बच्चों व उनकी शिक्षा हर किसी के निशाने पर है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर एक आरोप आए दिनों लगता रहता है कि वे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। शिक्षक स्कूलों में पहुंचते ही नहीं। वे स्कूलों से बिना बताए गायब रहते हैं। और जो चित्र बनता है वह ऐसा आभास देता है कि मानो बड़ी तादाद में शिक्षक स्कूलों से गायब रहते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि शिक्षकों की बड़ी तादाद स्कूल से गायब रहती है। क्या सचमुच सरकारी स्कूलों में शिक्षक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं?

इसी मसले को समझने के लिए एक अध्ययन 'टीचर एबसेंटिज़्म' शीर्षक से हाल ही में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की फील्ड रिसर्च टीम द्वारा किया गया है। इस अध्ययन का मकसद यह जानना-समझना है कि क्या सचमुच में शिक्षक स्कूलों से गायब रहते हैं। अध्ययन के परिणाम उन तमाम मान्यताओं को धत्ता बताते हैं। दरअसल, स्कूलों से केवल 2.5 फीसदी शिक्षक ही बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं। बाकी मामलों में शिक्षकों का स्कूल से अनुपस्थित रहने की वजह तंत्रगत है जो विविध कारणों से स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन एक अलाभकारी संगठन है। इसका लक्ष्य एक ऐसी पहल करना है जिससे न्यायसंगत, समतामूलक एवं मानवीय समाज के निर्माण में भागीदारी की जा सके। इसके लिए फाउंडेशन ने स्कूली शिक्षा को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र चुना है। वर्तमान में अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन देश के पांच राज्यों के लगभग 50 जिलों में सरकारी स्कूली शिक्षा के शिक्षकों के साथ कार्यरत है। लगभग 1000 से अधिक फाउण्डेशन के कार्यकर्ता पांच राज्यों के उन जिलों में कार्यरत हैं जो सामाजिक-आर्थिक मापदंड पर पिछड़े जिले माने जाते हैं। फाउण्डेशन पिछले लगभग डेढ़ दशक से सरकारी स्कूली तंत्र में कार्यरत है जहां एक ओर शिक्षकों, प्रधानाध्यापक व प्राचार्य, शैक्षिक अधिकारियों के साथ उनके पेशेवर विकास के मसलों पर कार्यरत हैं।

हाल ही में किए गए अध्ययन में यह समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में शिक्षक स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं। अगर शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहते भी हैं तो उसकी वजहें क्या हैं? अक्सर कोई स्कूल में जाता है तो वह शिक्षक को अनुपस्थित पाकर सामान्यीकरण कर बैठता है व नकारात्मक छवि गढ़ लेता है। यह पता करने की कोशिश नहीं की जाती कि कहीं शिक्षक अवकाश पर तो नहीं। अवकाश की पात्रता शिक्षक को होती है जो वर्ष में जरूरत पड़ने पर वह ले सकता है। इसी प्रकार से शिक्षक शासकीय कार्य से बीआरसी, विकास खंड, जन शिक्षा केंद्र या किसी अन्य कार्य से स्कूल से बाहर हो सकता/सकती है। जाहिर तौर पर शिक्षक की स्कूल में अनुपस्थिति कक्षा शिक्षण को प्रभावित करती है। मगर यह मान्यता कि शिक्षक बिना बताए स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, यह स्कूली शिक्षातंत्र के लिए दर्दनाक है। प्रस्तुत अध्ययन के नतीजे उन तमाम सहज धारणाओं को खारिज करते हैं जो शिक्षकों की छवि को नकारात्मक रूप में पेश करते हैं।

जिन जिलों व विकास खंडों में यह अध्ययन किया गया वहां अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की मौजूदगी है जो कि देश के काफी सुविधाहीन क्षेत्रों में आते हैं। इस अध्ययन में जिन स्कूलों का चुनाव किया गया वहां फाउण्डेशन की टीम उन स्कूलों के साथ कार्य करती रही है। नमूने में जिन स्कूलों का चयन किया गया उनमें ग्रामीण व शहरी, निम्न व उच्च प्राथमिक स्कूलों का खासा ख्याल रखा जहां दोनों का प्रतिनिधित्व हो। जिन छह राज्यों में यह अध्ययन किया गया वहां की कुल 619 स्कूलों में अध्ययन दल पहुंचा और 2891 शिक्षकों के आंकड़े प्राप्त किए। यह अध्ययन अगस्त-सितंबर माहों में किया गया, जब माना जाता है कि स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से प्रारंभ हो जाती है और कोई बड़े त्यौहार भी उस दौरान नहीं होते हैं। अध्ययन के लिए जो लोग स्कूलों में गए तो उसकी पूर्व सूचना स्कूल को नहीं दी गई थी। अध्ययन किए गए स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर आंकड़े दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षक स्कूल से बिना बताए मात्र 2.5 फीसदी ही अनुपस्थित रहते हैं। इनमें शामिल है कार्यालयीन कर्तव्य, अधिकृत अवकाश व बिना बताए अनुपस्थित रहना इत्यादि।

एक नजर तालिका पर

शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण

अनुपस्थिति का कारण	अनुपस्थिति
अधिकृत अवकाश	9.1
बिना कारण बताए स्कूल से अनुपस्थित	2.5
कार्यालयीन अकादमिक कर्तव्य पर	3.8
कार्यालयीन अन्य विभागीय कार्य	0.9
कार्यालयीन प्रशासनिक कर्तव्य पर	2.1
कुल	**18.9**

अध्ययन के इन आंकड़ों पर नज़र डालने पर तस्वीर का एक ऐसा पहलू सामने आता है जो सरसरी तौर पर किए गए अवलोकनों को खारिज करता है। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थिति का प्रतिशत 16.2 से लगाकर 22.6 तक जाता है। पता चलता है कि महिला शिक्षिकाएं बनिस्बत पुरूष शिक्षकों के स्कूल में कम अनुपस्थित रहती हैं।

इस तस्वीर को देखने पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस अध्ययन में यह देखा गया कि आखिर शिक्षकों के अनुपस्थित रहने की वजहें क्या हैं।

कुल मिलाकर शिक्षक अगर स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वजहें उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई वजहें हैं। बिना कारण बताए स्कूल से अनुपस्थित रहने का प्रतिशत 2.5 है जबकि सकल अनुपस्थिति 20 प्रतिशत की रेंज में है।

वास्तव में स्कूल से बिना बताए अनुपस्थित रहना एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है। अध्ययन बताता है कि शिक्षक अगर स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी वजहें कहीं अधिक तंत्रगत है। तंत्रगत कारणों से शिक्षक अपने स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं जिसका प्रभाव कक्षा शिक्षण पर पड़ता है जिसकी तरफ शिक्षा विभाग की नज़र नहीं जाती।

दरअसल, शिक्षक की अनुपस्थिति को एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाना सरकारी स्कूली शिक्षातंत्र को और बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देख सकते हैं कि शिक्षकों की अनुपस्थिति को रोकने के लिए सरकार की ओर से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया। बायोमेट्रिक प्रणाली में शिक्षक को अपने प्रमाण देने होते हैं कि वह स्कूल में मौजूद है या नहीं। जहां शिक्षक मोबाइल के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली की यह व्यवस्था शिक्षकों पर शक करने से ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार शिक्षकों पर मुहर लगा दी जाती है कि सभी शिक्षक बेईमान हैं। जबकि अध्ययन बताता है कि केवल 2.5 फीसदी शिक्षक ही बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं। बाकी के शिक्षक तंत्रगत कार्य से कर्तव्य पर रहते हुए स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं।

गुणात्मक अध्ययन बताते हैं वाकई में शिक्षक अनुपस्थिति इतने खतरनाक स्तर पर नहीं है जैसा कि वर्तमान नीति विमर्श में कहा जा रहा है। दूसरे स्तर पर ये गुणात्मक अध्ययन चुनौतियों, प्रणालीगत व व्यक्ति को लेकर एक अंतर्दृष्टि देते हैं जो यह दर्शाता है कि शासकीयतंत्र में शिक्षक को इन समस्याओं से नियमित रूप से निपटना है। ये मिसालें यह भी दर्शाती हैं कि इन सब चुनौतियों के बावजूद वे अपने कार्य के प्रति समर्पण व अनुकरणीय मिसाल पेश करते हैं।

एक तरफ जहां इस अध्ययन के तहत स्कूलों से अनुपस्थिति को लेकर आंकड़े प्राप्त कर विश्लेषण किए गए वहीं दूसरी ओर स्कूलों के शिक्षकों से बातचीत की और उसे रेकार्ड किया। अध्ययन के दौरान की गई केस स्टडी सरकारी स्कूलतंत्र के शिक्षकों के कार्य को लेकर वर्तमान की सच्चाइयों की बहुत बारीकी से छानबीन करती है। ये केस स्टडी बताती है कि शिक्षक प्रतिकूल हालातों व व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद एक ईमानदार पेशेवर के रूप में कार्य करते हैं।

इन चर्चाओं में समझ में आया कि विविध समस्याओं व विपरीत हालातों जिसमें शामिल है स्कूल का दूरस्थ होना, शिक्षकों की कमी, स्कूल तक पहुंचने में दिक्कत, स्कूल में पर्याप्त साधन सामग्री का अभाव, बहुकक्षागत ढांचा और हाशियाकृत समुदाय जो कि अपने बच्चों को घर पर पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे ही स्कूलों में से यहां कुछ स्कूलों की एक झलक प्रस्तुत है जो हमें सरकारी स्कूलों को लेकर उम्मीद जगाती है कि जहां चाह है वहां राह है।

केस स्टडी: 1

छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी विकास खंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव लालपानी पंचायत में आता है। इस गांव के ज्यादातर लोग खेतिहर मजदूर हैं। प्रमुख रोड से गांव 5 किलोमीटर अंदर है। इसलिए इस गांव तक आना चुनौतीपूर्ण है। यहां सार्वजनिक बसों इत्यादि का अभाव है। इस गांव में स्कूल की स्थापना का संयुक्त श्रेय समर्पित शिक्षकों व चुनिंदा समुदाय के सदस्यों को जाता है। वर्तमान प्रधानाध्यापक सुकेश(परिवर्तित नाम)1983 में इस स्कूल में ज्वाइन किए। इसके पहले वे तीन अन्य स्कूलों में कार्य कर चुके थे। बताते हैं कि इसके पहले वे जिन स्कूलों में अध्यापनरत थे वहां 12 किलोमीटर रोजाना चलकर जाते थे। उस गांव में बिजली भी नहीं थी। उसी दौरान उन्हें लगा कि उसी गांव में उन्हें रहना चाहिए। सुकेश के अनुसार, समुदाय के लोगों की उनके बच्चों की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन विपरीत हालातों के चलते सुकेश ने बच्चों व समुदाय के साथ जमकर काम किया व स्कूल को जमाया। 2008 में जब सुकेश ने माध्यमिक स्कूल को ज्वाइन किया तब स्कूल में कुल 65 छात्र थे। एक वक्त था तब स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 20 फीसदी तक कम हो गई थी। पालक व समुदाय में शिक्षा के प्रति दिलचस्पी नहीं थी। वैसे बच्चे भी स्कूल में आने के प्रति प्रेरित नहीं थे। शिक्षा के प्रति अरुचि खासकर आदिवासी बच्चों में कहीं अधिक थी। सुकेश बताते हैं कि उन्होंने तय किया कि वे साल के प्रारंभ में बच्चों के घरों को जाएंगे व उनके माता-पिता से चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों का स्कूल आना क्यों जरूरी है। सुकेश के अनुसार, तय किया कि हम चर्चा करके समझाएंगे कि अगर आपके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है तो उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। इसके लिए स्कूल का अपना महत्व है। हम बच्चों से भी बात करेंगे व उन्हें स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों से बातचीत करते हुए हमें 'बच्चा' बनना होगा, तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी। एक अन्य शिक्षक ने कहा -प्रधानाध्यापक ने काफी काम इस पर किया मगर अभी भी अनेक समस्याएं हैं। इसके बाद हमने पालकों, बच्चों, समुदाय व स्कूल प्रबंधन समिति के साथ काम किया और नतीजा हमारे सामने है।उसी दौरान हमने यह महसूस किया कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), समुदाय के साथ जुड़ाव का उम्दा माध्यम है व एसएमसी के अंदर ही जो औरतें हैं वे बच्चों को प्रभावित करने का बेहतर जरिया हो सकती हैं। शिक्षक बताते हैं कि महिलाओं को शामिल करके एसएमसी को सशक्त बनाते हुए उसे सक्रिय बनाया गया। सुकेश बताते हैं कि इन बैठकों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर काफी काम किया। वे आगे कहते हैं कि हमने यह महसूस किया कि अगर हम महिलाओं को जागरूक बना दें तो शायद यह काफी फर्क पैदा कर सकता है। हमने उन्हें यह भी बताया कि यह आपका स्कूल है हमारा नहीं। शनै: शनै: एसएमसी नियमित होती चली गई।

सन् 2010 तक समुदाय में स्कूल के प्रति जागरूकता को लेकर चीजों में सुधार होता गया। अब समुदाय, स्कूल की बेहतरी के लिए निर्णय लेने में शामिल होता है व अपना योगदान भी कर रहा है। स्कूल में सामग्री व खेल का मैदान, कक्षाओं के लिए कमरे वगैरह है। मगर शौचालयों में पानी नहीं होने के कारण वे इस्तेमाल में नहीं आते थे। एसएमसी सदस्यों, शिक्षक व समुदाय के लोगों ने पंचायत से अनुरोध किया कि वे इस बारे में कुछ करें। वर्तमान में इस स्कूल में पहली से सातवीं तक 41 बच्चे व चार शिक्षक हैं।

उम्मीद की किरणें: जिन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया

केस स्टडी: 2

उत्तराखंड राज्य का एक गांव जहां की जनसंख्या 660 व घरों की संख्या 118 है। यहां का लिंग अनुपात 1025 औरतों पर 1000 पुरुष हैं। यहां की साक्षरता दर 77 फीसदी है। यह गांव विकासखंड मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव को विकास खंड से जोड़ने के लिए यातायात नहीं है। गांव तक आने के लिए अपने वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक स्कूल आने के लिए साझी टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। बरसात के दिनों में जब टैक्सी नहीं चलती तब शिक्षकों को गांव में ही रुकना पड़ता है।

समुदाय के लोग खेती व डेयरी का काम करते हैं। साल के अधिकांश दिनों में वे ऊंचे पहाड़ों पर अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं व साल के दो-तीन महीनों के लिए गांव में लौटते हैं। इस कारण से पालकगण स्कूल लगने के दौरान गांव में नहीं रह पाते। शिक्षक बताते हैं कि इस दौरान वे अपने आपको कहीं अधिक जिम्मेदार समझते हैं जहां बच्चों के माता-पिता गांव में नहीं होते हैं। अगर इस दौरान माता-पिता बच्चों की देखरेख नहीं कर पाते हैं तो फिर शिक्षकों को पालक की भूमिका अदा करनी चाहिए व उन्हें अपने बच्चों के माफिक समझना चाहिए।

इस स्कूल में तीन शिक्षक हैं - प्रधानाध्यापक शालिनी, व दो सहायक शिक्षक अर्चना व प्रीत। प्रधानाध्यापिका इस स्कूल में पिछले दस वर्षों से हैं। कुल मिलाकर उनका स्कूली शिक्षा में 26 सालों का अनुभव है। चूंकि शालिनी का स्कूल से लंबा जुड़ाव है इसलिए वे समुदाय के लोगों व बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हैं। बाकी दोनों शिक्षिकाओं का भी कई सालों का अनुभव है।

बच्चों के प्रति उन शिक्षिकाओं का जुड़ाव कई तरह से प्रकट होता है। शिक्षक बच्चों के साथ ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं जिन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। वे बच्चों के लिए सत्र के आरंभ में तीन महीनों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करते हैं जो प्राथमिक स्कूल से यहां आते हैं और उन्हें मदद की जरूरत होती है। शिक्षिका बताती हैं कि वे कोशिश करती हैं कि सभी बच्चों पर बराबरी से ध्यान दें जिनमें विशेष जरूरत वाले भी होते हैं। वे इसके लिए कई रणनीतियां अपनाती हैं। भाषा शिक्षक होने के नाते, वे उन्हें समूह में कार्य करने को देती है। वे कहती हैं कि मेरा काम मेरे बच्चों में प्रतिबिंबित होता है। वे यह भी कहती है कि बच्चे उनके प्यार के बदौलत सीखते हैं, अगर आप बच्चों को प्यार करते हैं तो वे भी आपको चाहते हैं।

स्कूल में एसएमसी है जहां पालक समय की कमी के कारण शामिल नहीं हो पाते हैं मगर प्रधानाध्यापिका बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट नियमित रूप से पालकों के साथ साझा करती हैं। कई बार शिक्षिकाओं में निराशा भी होती है जब बच्चों के पालक दिलचस्पी नहीं लेते हैं। एसएमसी प्रमुख संजय जो कि गांव के प्रभावशाली सदस्य हैं वे बताते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण पालकों का अपने बच्चों व शिक्षा के प्रति यह उपेक्षित रवैया है। पालकों का मानना है कि स्कूल को ही बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लिहाजा शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए कि अपने शिक्षकीय दायित्व की जिम्मेदारी के चलते वे बच्चों का खासा ख्याल रखते हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी की बदौलत ही इस गांव के बच्चे पास के इंटर कॉलेज तक पिछले कई सालों से पहुंच पा रहे हैं। एसएमसी, स्कूल को बेहतर बनाने के लिए काफी काम करती हैं। उनका मानना है कि 'यह स्कूल हमारा प्यारा स्कूल है और हम इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं।'

केस स्टडी: 3

राजस्थान के दूरस्थ इलाके के एक गांव में हीरालाल नामक प्रधानाध्यापक ने स्कूल की दशा ही बदल डाली। वे यहां स्कूल के प्रारंभ होने के दौरान से ही हैं। हीरालाल के प्रयासों से ही यह स्कूल स्थापित हुआ और नियमित रूप से संचालित हो रहा है। सन् 2007 तक जब स्कूल का भवन नहीं था, उन्होंने अपने पास से खर्च करके स्कूल के लिए मकान किराए पर लिया और चलाया। वे याद करते हुए बताते हैं कि 'उन शुरूआत के सालों में न तो किराए का कमरा स्कूल चलाने के लिए दिया न ही कोई जगह दी। मैंने 200 रुपए माह पर कमरा किराए पर लिया और स्कूल चलाया।' एक अन्य पेरा शिक्षक जब वहां पदस्थ हो गए, उसके बाद वहां दोनों ने जमकर काम किया और स्कूल में बच्चों का नामांकन भी बढ़ा।

शिक्षक बताते हैं कि समुदाय के लोग शुरूआती सालों में बच्चों को स्कूल भेजने में आनाकानी करते थे। वे कहते कि हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि स्कूल दूर है और कब्रगाह सामने हैं। गांव वालों को काफी समझाया-बुझाया और अब वे बच्चों को स्कूल में भेजने लगे हैं। मगर फिर भी चूंकि कोई मौत हो जाती है तो डर के मारे बच्चों की उपस्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। 2008 में प्रधानाध्यापक की पहल पर जब स्कूल का भवन बन गया तो फिर स्कूल में बच्चों के नामांकन में काफी बढ़ोतरी हुई। अध्ययन के जरिए खुलासा होता है कि सन् 2008-2009 में उस स्कूल में 23 बच्चों का नामांकन था जो 2015-2016 में 82 हो गया।

स्कूली शिक्षा को लेकर हमारे अधिकारियों ने जो छवि बनाई है उस छवि को यह अध्ययन तोड़ता है। हमें शिक्षकों पर दोष देने के बजाय उन पर भरोसा जताने की आवश्यकता है। यह भी सच है कि 2.5 फीसदी शिक्षक जो बिना बताए या कि बिना अवकाश लिए स्कूल से गायब हैं यह अपराध की श्रेणी में आता है। मगर यह आंकड़ा इतना भयानक नहीं है जो बताया जा रहा है।हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं। अधिकांश मामलों में शिक्षकों को हम दोषी ठहराते हैं जिसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए शिक्षा का तंत्र भी दोषी है। वर्तमान के विमर्श शिक्षक को ही दोषी ठहराते हुए उसकी अनुपस्थिति को केंद्र में रखते हैं जिसके कारण बायोमेट्रिक्स जैसी चीजों से दबाव बनाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा में कुशलता व जवाबदेही की जो चर्चा वर्तमान में हो रही है वे तंत्र की रोजमर्रा की सच्चाई व विभिन्न कारक जो शिक्षक की स्कूल में उपस्थिति को प्रभावित करते हैं, उनकी उपेक्षा करती हैं। आज जरूरत है कि शिक्षकों के बारे में जो छवि बनाई जा रही है उस पर इस अध्ययन की रोशनी में गौर करें व एक नए सिरे से शिक्षकों के प्रति राय बनाएं। साथ ही यह भी जरूरी है कि जो शिक्षक बेहतर कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को सार्वजनिक किया जाए ताकि सरकारी स्कूलीतंत्र में सकारात्मकता की बयार आए।

संपर्क:
द्वारा- राजेश चंद्रशेखर बड़ोले, पावर हाउस के पीछे,
नूतन नगर कॉलोनी,पूरण सेठ की चाल,
खरगोन मध्यप्रदेश 451001